अति नगरीकरण (Over-Urbanisation)

नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या को स्थान प्रदान करने अथवा अनेक अन्य नागरिक सुविधाएँ जैसे स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय आदि उपलब्ध कराने संबंधी दायित्व एवं सीमाएँ होती हैं। एक निश्चित जनसंख्या के पश्चात् ये सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रशासन के लिये भी कठिन कार्य हो जाता है। उदाहरणार्थ- मुम्बई, कोलकाता आदि नगरों की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है जिसे नियंत्रित करना एवं आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना प्रशासन की क्षमता से बाहर हो गया है। यह विशेषता अतिनगरीकरण को चित्रित करती है।

उपनगरीकरण (Sub Urbanisation)

महानगरों में होने वाले अतिनगरीकरण से जुड़ी हुई दूसरी विशेषता उपनगरीकरण की है। जब नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का आधिक्य हो जाता है, भीड़-भाड़ हो जाती है तब उपनगरीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिल्ली नगर उपनगरीकरण का एक उत्तम उदाहरण है, जहाँ उपनगरीकरण की प्रवृत्ति इसके चारों ओर फैल रही है। उपनगरीकरण से तात्पर्य नगर के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र को नगर में सम्मिलित किये जाने से है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र के नगरीकरण से है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ देखने को मिलती हैं -

(अ) भूमि के गैर-कृषक (नगरीय) प्रयोग में तीव्र-वृद्धि।

(ब) नगर के निकटवर्ती क्षेत्र को नगर की नगरपालिका सीमाओं में सम्मिलित करना।

(स) नगर और उसके आस-पास के क्षेत्रों के मध्य सभी प्रकार की व्यापक संचार-व्यवस्था।

इस प्रकार भारत में नगरीय जनसंख्या का विकास एक ढंग से नहीं हुआ है। विभिन्न राज्यों में नगरीकरण में विविधता देखने को मिलती है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यह विविधता विभिन्न प्रकार के नगरों में नगरीकरण की प्रवृत्ति में देखने को मिलती है। एक उदाहरण के रूप में पुनः यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। 1981 में भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.3 था अर्थात् भारत में कुल जनसंख्या का 23.3 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी। विश्व के अनेक देशों की नगरीय जनसंख्या को देखते हुए इसे अनुकूल नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, यदि हम भारत में एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की ओर दृष्टिपात करें तो इन नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या के 60 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या निवास करती थी।

यद्यपि भारत को गाँवों के देश के रूप में माना जाता है तथापि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से भी यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। 1991 की जनगणना के अनुसार 23 करोड़ से अधिक लोग भारत के नगरों में निवास करते थे। नगरीय जनसंख्या वृद्धि की दर कुल जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक तीव्र रही है। यदि भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में

Scanned with CamScanner

देखा जाय तो सन् 1901 से 1981 तक की अवधि में भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या में ढाई गुणा वृद्धि हुई है इस अवधि में नगरीय जनसंख्या 6 गुणा बढ़ी है। सन् 1971-81 की अवधि में नगरीय जनसंख्या 3.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी थी। 1991 के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की वार्षिक वृद्धि की दर 4.68 प्रतिशत रही है।

तृतीय विश्व के देशों में नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं कि नगरीय जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के फलस्वरूप जनसुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तथा स्थानीय प्रशासन इस विकट परिस्थिति का सामना कर पाने में असमर्थ हो गया है। फिर भी नगर-नियोजक एवं प्रशासक इस विकट परिस्थिति के अधिक विकृत होने से रोकने के प्रयासों मे निरंतर संलग्न हैं। अनेक प्रकार की नगरीय विकास योजनाएँ भावी जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखकर ही अस्तित्व में आ रही हैं।

वर्तमान में भारतीय नगरीय जनसंख्या में निम्न प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं -

(1) बड़ें नगरों (महानगरों) की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि।

(2) छोटे कस्बों (नगरों) में कमी अथवा धीमी वृद्धि।

(3) उन क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जहाँ अत्यधिक औद्योगिकरण-हुआ है। उदाहरण के तौर पर -

(I) पश्चिमी क्षेत्र	इसमें अहमदाबाद, मुम्बई तथा पुणे को सम्मिलित किया जा सकता है।
(II) दक्षिणी क्षेत्र	इसमें बैंगलोर तथा चैन्नई का क्षेत्र आता है।
(III) पूर्वी क्षेत्र	कोलकाता तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र
(IV) उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली तथा कानपुर

(4) कतिपय राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, असम (पूर्वोत्तर राज्यों समेत) तथा केरल आदि में नगरीकरण की दर पर्याप्त नीची है।

(5) भारत के विभिन्न भागों में नगरीकरण (नगरीय जनसंख्या) की असामान्य वृद्धि का कारण न केवल जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है अपितु इसके साथ ही औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली से सम्बन्धित सरकार की विभिन्न नीतियाँ भी बनी हैं जो वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक तेज गति से बढ़ने के लिये प्रेरित करती हैं तथा इसके अतिरिक्त यातायात संबंधी नीतियाँ भी हैं जो लोगों को तथा माल को महानगरों की ओर ले जाने के लिये लालायित एवं आकर्षित करती हैं।

(6) कुछ क्षेत्रों जैसे कोलकाता, मुम्बई तथा दिल्ली में जनसंख्या का भारी दबाव है तथा अतिनगरीकरण की स्थिति बन गई है।

Scanned with CamScanner

नगरीय जनसंख्या के तथ्यों की आवश्यकता

नगरीय जनसंख्या संबंधी तथ्य अनेक दृष्टि से अपनी महत्ता रखते हैं। ऐसे देशों में जहाँ तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा है, योजना तथा नीति-निर्माण के लिये प्रभावकारी तथ्य संकलन तथा विश्लेषण विधि की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये नगरीकरण से संबंधित तथ्य निम्नलिखित रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं -

1. प्रत्येक नगर एवं कस्बे हेतु मास्टर-प्लान बनाने के लिये।
2. नगरीय योजनाएँ बनाने के लिये, जिसमें भावी आवश्यकताओं जैसे- भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यावरण संबंधी योजनाएँ तथा जनशक्ति आदि के क्षेत्रों का दिग्दर्शन किया जा सके।
3. उद्योग-विकास, नये कस्बों का निर्माण तथा संतुलित भौगोलिक विकास के लिये।
4. आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि से उद्योग तक हुए परिवर्तन के मध्य आने वाली कठिनाइयों को समझने तथा उन्हें दूर करने के लिये।
5. आंतरिक प्रवास विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर पलायन में आने वाली अड़चनों को समझने के लिये।
6. पंचवर्षीय-योजनाओं के संदर्भ में संपूर्ण नगरीय तथा क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिये।

अधिक विकसित देशों के नगरीकरण से संबंधित अधिकांश रचनाओं में आवास, कच्ची बस्तियों तथा नगरीय नवीनीकरण पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। हाल ही में इनमें हटकर पर्यावरण को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। भारत के संदर्भ में भी नगरीकरण का अध्ययन आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के संदर्भ में किये जाने की अधिकाधिक आवश्यकता है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि नगरों, विशेषकर महानगरों को अनावश्यक भीड़भाड़ से मुक्त किया जावे। उन्मुक्त प्रवास अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जाये, कच्ची बस्ती विकास को रोका जाये। इस दिशा में स्थानीय प्रशासन में अत्यधिक सक्रियता लाने की आवश्यकता है।

Scanned with CamScanner